भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 449

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

ग्रोथ हब कार्यक्रम

449. **श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों को विकास केन्द्र कार्यक्रम के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य के उन शहरों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त कार्यक्रम के लिए चुना गया है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों के लिए किए गए अध्ययन और इन अध्ययनों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार इस अध्ययन का उपयोग आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) नीति आयोग ने 2023 में शहरों के विकास के लिए विकास के इंजन के रूप में ग्रोथ हब पहल की परिकल्पना की थी। इसका दृष्टिकोण शहरी सीमाओं से परे जाने वाले शहरी क्षेत्रों की पहचान करना और तीन प्रमुख घटकों (i) आर्थिक और निवेश योजना; (ii) जीवन की गुणवत्ता; तथा

(iii) समावेशिता और संधारणीयता प्लान के आधार पर एक आर्थिक प्लान विकसित करना था। प्रक्रिया टेम्पलेट विकसित करने के लिए चार पायलट स्थानों का चयन किया गया, अर्थात मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), वाराणसी, सूरत और विशाखापट्टनम जिन्हें आर्थिक क्षेत्र के केंद्रों के रूप में निर्धारित किया गया था। प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में, 5-चरण प्रक्रिया अर्थात (i) जैसा है निदान (as is diagnostic), (ii) एसडब्ल्यूओटी, बंदोबस्ती और क्षमता विश्लेषण, (iii) आर्थिक दूरदर्शिता, (iv) महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि के घटकों का चयन (V) कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के आधार पर विशिष्ट आर्थिक मास्टर प्लान विकसित किए गए हैं। यह परियोजना रिपोर्ट महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नीति-निर्धारकों के माध्यम से विशिष्ट अन्तःक्षेप पेश करती है। यह पहल राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम है, जिसमें नीति आयोग संबंधित राज्य सरकारों और ज्ञान भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। आर्थिक योजना तैयार करने हेतु आंध्र प्रदेश के मामले में, उक्त कार्यक्रम के लिए विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र (वीईआर) का चयन किया गया है, जिसमें सात जिले अर्थात अनकापल्ली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम मन्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी शामिल है।

(च) और (छ) विशाखापट्टनम आर्थिक क्षेत्र हेतु आर्थिक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।

*****